भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2307

12.03.2026 को उत्तर के लिए

प्रदूषण नियंत्रण और एनसीएपी के लिए आवंटन

2307 **श्री एस. निरंजन रेड्डी:**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले वर्ष के संशोधित प्राक्कलनों की तुलना में प्रदूषण नियंत्रण और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के लिए आवंटन में कमी (1,300 करोड़ रूपए से घटकर 1,091 करोड़ रूपए) के क्या कारण है;

(ख) बजटीय संसाधनों की पूर्ति के लिए मंत्रालय ने कितना अंतरराष्ट्रीय जलवायु वित्त, ग्रीन बॉन्ड, बहुपक्षीय वित्तपोषण और निजी पूंजी जुटाई है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान एनसीएपी के तहत राज्यों को प्रदान किए गए प्रदर्शन-आधारित वित्तीय प्रोत्साहनों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क): केंद्रीय क्षेत्र योजना 'प्रदूषण नियंत्रण' के लिए आवंटन वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान (बीई) में 853.9 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान (आरई) में 1300 करोड़ रुपये हो गया है। वर्ष 2026-27 के बजट अनुमान में 1091 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान से अधिक है।

(ख): भारत के जलवायु संबंधी कार्य मुख्य रूप से संबंधित मंत्रालयों/विभागों के बजटीय आवंटन द्वारा वित्त पोषित हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एनएपीसीसी) से संबंधित नौ मिशनों को संस्थागत बनाया है। भारत ने देश के भीतर जलवायु संबंधी कार्यों के वित्तपोषण के लिए हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) और अनुकूलन कोष (एएफ) जैसे बहुपक्षीय कोषों के साथ भी सहभागिता की है। अब तक, जीसीएफ द्वारा जल, स्वच्छ ऊर्जा, तटीय, आजीविका, परिवहन,

मध्यम और लघु उद्यमों और जलवायु स्टार्ट-अप्स सहित क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने और अनुकूलन के लिए कुल 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आवंटन के साथ भारत को सोलह (16) परियोजनाओ/कार्यक्रमों को मंजूरी दी गई है। देश ने अनुकूलन कोष से संसाधनों का उपयोग किया है। परियोजनाओं की कुल राशि 16.86 मिलियन अमेरिकी डॉलर है जिसमें खाद्य सुरक्षा, वन, कृषि, जल प्रबंधन और तटीय प्रबंधन जैसे क्षेत्र शामिल हैं। जलवायु संबंधी कार्यों के वित्तपोषण के लिए भारत वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) के साथ भी सहभागिता का रहा है।

आर्थिक कार्य विभाग ने पात्र हरित परियोजनाओं के लिए व्यय को वित्तपोषित करने और/या पुनर्वित्तपोषित करने हेतु 'सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के लिए रूपरेखा' जारी की है।

(ग): वर्ष 2022-23 से अब तक राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के अंतर्गत 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 130 शहरों को प्रदान किए गए वायु गुणवत्ता अनुदान का राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में संलग्न है।

अनुलग्नक -I

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) और वर्ष 2022-23 से आज तक XVवें वित्त आयोग के वायु गुणवत्ता अनुदान के तहत 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 130 शहरों को प्रदान किए गए वायु गुणवत्ता अनुदान का कार्य निष्पादन-संबंधी राज्यवार ब्यौरा:

क्रम संख्या .	राज्य	जारी की गई राशि (करोड़ रुपए में)
1.	आंध्र प्रदेश	238.57
2.	असम	96.36
3.	बिहार	69.97
4.	चंडीगढ़	25.48
5.	छत्तीसगढ	114.19
6.	दिल्ली	70.11
7.	गुजरात	648.27
8.	हरियाणा	52.89
9.	हिमाचल प्रदेश	12.12
10.	जम्मू और कश्मीर	167.04
11.	झारखंड	42
12.	कर्नाटक	184.44
13.	मध्य प्रदेश	362.33
14.	महाराष्ट्र	497.35
15.	मेघालय	9.16
16.	नागालैंड	24.08
17.	ओडिशा	91.68
18.	पंजाब	248.67
19.	राजस्थान	261.59
20.	तमिलनाडु	421.89
21.	तेलंगाना	373.12
22.	उत्तर प्रदेश	2147.71
23.	उत्तराखंड	86.18
24.	पश्चिम बंगाल	723.27
कुल		**6968.47**